और... एक शे'र

उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है
-मिर्ज़ा ग़ालिब

लोकमत समाचार
छिंदवाड़ा, रविवार, 3 मई 2015

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं. ■ अज्ञात

संपादकीय

मेडिकल की रिक्तियों पर हाईकोर्ट की नजर

महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों की बड़ी संख्या में रिक्तियां चिंता का विषय तो है ही, सरकार की उदासीनता भी दर्शाती है. एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ ही बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात करते नहीं अघाती, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेजों) का यह हाल कि जहां पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं हैं, सरकार की कथनी और करनी में इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? मेडिकल कॉलेजों में रिक्तियों को भरने पर सरकार कितनी संजीदा है यह सालों से खाली पड़े पदों को देख कर समझा जा सकता है. मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यह सरकार को अच्छी तरह पता है, फिर भी रिक्तियों को भरने में इस तरह की हीलाहवाली समझ से परे है. अक्सर संसाधनों की कमी मेडिकल कॉलेज खोलने में एक बड़ी बाधा से कम नहीं है, इसके बावजूद अगर कहीं अनुमति मिल भी गई तो वहां तत्काल उसे पूरा करने का प्रयास भी नहीं दिखाई देता. ऐसे कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा? आधा-अधूरा ज्ञान लेकर चिकित्सा क्षेत्र में पदार्पण करने वाले डॉक्टरों की सेवा 'नीम हकीम खतरा-ए-जान' को ही चरितार्थ करती रहेगी. यहां सीधे तौर पर मरीज की जिंदगी का सवाल है. इसीलिए तो बंबई हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को प्राथमिकता के आधार पर प्राध्यापकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने का आदेश दिया. राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के 89 और एसोसिएट प्रोफेसरों के 287 पद रिक्त हैं. हालांकि सरकार ने अदालत को 117 पदों के लिए विज्ञापन देने की जानकारी दी है. यह अच्छी बात है कि इन रिक्तियों के मद्देनजर सरकार ने मेडिकल प्राध्यापकों की नियुक्ति को डिविजनल कॉडर नियमन से छूट देने का एक बड़ा फैसला लिया है. अब सवाल यह है कि क्या तीन महीने में सारी रिक्तियां भर पाएंगी? यह कैसी विडंबना है कि रिक्तियों को भरने के लिए भी हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों का नितांत अभाव किसी भी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है.मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों का होना चिकित्सा परिषद के मानकों में अनिवार्य किया गया है तो उसे किसी भी सूरत में यूं ही रिक्त पड़ा नहीं होना चाहिए. अब सवाल यह है कि इन रिक्तियों के लिए दोषी किसे माना जाए? अंतिम स्थिति में जिम्मेदारी सरकार की ही है. अतः उसे अद्यतन जानकारी अवश्य होनी चाहिए. अब यह सरकार ही बताए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये पद खाली क्यों पड़े रहे? ■■

टूटने पर

ठंडी रात... सन्नाटे भरी! गांव लगभग सो चुका है - वैसे भी गांव में प्रायः सभी जल्दी सो जाते हैं. वे दोनों जाग रहे हैं. एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत. जलती हुई लकड़ियों को घेरे बैठे हुए. लालटेन जल रही है धीमी. बहुत धीमी! लालटेन का पीला प्रकाश उन दोनों के चेहरों पर पड़ रहा है. बाहर ठंड!... सन्नाटा!!

''बड़का मिलो थो आज... बजार में टकरा गओ'', बूढ़ा बोला.

लघुकथा

पवन शर्मा

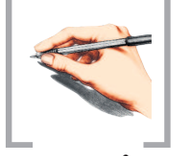

औरत चौंक जाती है, ''कुछ कह रओ थो?''

''कुछ नईं.. हाल-चाल भर पूछो थो बाने. बता दिए... सब ठीक-ठाक है... और का कहतो मैं.''

''बचना के हाल-चाल पूछे रहे?''

''कहबे लगो कि अम्मा की याद बेजा करत है.''

''काए नईं करे... दिन-रात तो मोसे ही लिपटो रहत थो. बाकी दादी जो हूं. जब से अलग भओ है, तब से सूरत नई दिखाई...'' बूढ़ी औरत की आवाज पिघलने लगती है, ''लगत है, अपनी मांएं भी भूल गओ. नईं तो सूरत तो दिखा ही सकत है. और कछू कह रओ थो?... बहू कैसी है? पूछे थे?''

''तू फिर काए के लाने मर रही है बाकी याद में!'' बूढ़े की आवाज में हल्का क्रोध था.

''मौड़ा है मेरो... जा के मारे.'' बूढ़ी औरत की आवाज भीग रही थी, नम... ओस की बूंद की तरह.

''ऐसो मौड़ा भी का काम को. बुड्ढे -बुढ़िया ऐ अकेलो छोड़ दओ, और मेहरिया के कहवे पे अलग रहन लगो. जानत है, आज कह रओ थो कि...'' बूढ़े की आवाज तल्ख होने लगी, ''...कि खेत में से मेरो हिस्सा मोए दे दो, तो बाय बेच के कछू धन्धा कर लेऊं.''

अचानक जलती हुई लकड़ी चटक उठी. सन्नाटा क्षणभर के लिए भंग हो गया था. ■■

भूकंप से तबाही की वजह मानवीय गलती

केशब पौडेल
वरिष्ठ पत्रकार

काठमांडू के मुख्य शहर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित गोंगाबू निवासी शंकरमन महार्जन 25 अप्रैल को आए प्रलयंकारी भूकंप के बाद से बेटे, पत्नी और अपने मकान के किरायेदारों को तलाश रहे हैं. इस आपदा में उनकी 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है. उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनके अपने लोग जीवित होंगे. शंकरमन ने यदि पड़ोसियों की सलाह मानी होती और इमारत निर्माण के नियमों का पालन किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती. फिलहाल सरकारी पुनर्वास शिविर में रह रहे शंकरमन कहते हैं, ''यह मेरी गलतफहमी थी कि सीमेंट और लोहे से बनी इमारतों का भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ सकते. मैं एक झटके में ही लखपति से गरीब बन गया हूं.''

काठमांडू से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित स्वयंभू क्षेत्र निवासी लक्ष्मी बहादुर गुरुंग की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है. हालांकि गुरुंग के परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन भूकंप में उन्होंने पांच मंजिला इमारत के धराशायी होने के साथ ही जीवनभर की कमाई भी कुछ ही पलों में गंवा दी. गुरुंग कहते हैं, ''मैं नहीं जानता कि अब किस तरह से अपना कर्ज चुका पाऊंगा.'' नेपाल में भूकंप के बाद महार्जन और गुरुंग के साथ ही हजारों लोग कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं.

नेपाल के नीतिनिर्माता और उनका क्रियान्वयन करनेवाला प्रशासन भी वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार हैं. हालांकि नेपाल ने वर्ष 1988 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद पहली बार इमारत निर्माण के मानक तय किए थे और नियम बनाए थे, लेकिन इन नियमों का पालन कोई नहीं करता. नेपाल सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के चेयरमैन रह चुके पूर्व गृह मंत्री गोविंदराज जोशी कहते हैं, ''यह दर्शाता है कि भूकंप के बाद के हालात से निपटने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है. सरकार सिर्फ प्रचार करने में व्यस्त है. यह इमारत निर्माण के नियमों को क्रियान्वित करने में सरकार की नाकामी ही है.''

जागरूकता की कमी

यदि हम नेपाल के हालिया 7.6 की तीव्रता के भूकंप और जापान में वर्ष 2011 में आए 9.1 की तीव्रता के भूकंप के बीच तुलना करें तो हमें तबाही और हताहतों की संख्या में बड़ा फर्क नजर आता है. जापान में आया भूकंप काफी बड़ा था, लेकिन इसमें काफी कम लोग- कहें कि लगभग 100 लोग ही हताहत हुए. जापान की भूकंप से निपटने की तकनीक, बेहतर योजना और जागरूकता के कारण वहां काफी कम तबाही हुई. नेपाल इन बातों में पीछे रह गया.

> यहां कई इमारतें ऐसी हैं जिनका निर्माण 1934 में आए भूकंप के मलबे से निकली ईंटों और लकड़ियों से किया गया है. यह हकीकत है कि भूकंप लोगों को नहीं मारते लापरवाही से बनाई गई इमारतें उन्हें मारती हैं...

यह दर्शाता है कि फर्क भूकंप की तीव्रता से नहीं, बल्कि जागरूकता के स्तर और इमारतों के निर्माण की गुणवत्ता की वजह से पड़ता है. भूकंप पृथ्वी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इससे होने वाली तबाही लोगों द्वारा किए गए निर्माणकार्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. नेपाल में हुई तबाही यह दिखाती है कि विशेषज्ञों की राय की उपेक्षा करने पर कैसे कोई शहर बरबाद हो सकता है. चुनाव के जरिए निर्वाचित निकायों और इमारत निर्माण नियामक इकाई के अभाव में पिछले 15 वर्षों में यहां हालात बद से बदतर होते चले गए और घटिया निर्माण लगातार बढ़ता गया. लगभग 45 लाख से अधिक की आबादी वाली काठमांडू घाटी दुनिया की सबसे बेतरतीब उपनगरीय बस्ती बन गई है.

इस संबंध में जताई गई तमाम आशंकाएं 25 अप्रैल को सही साबित हुईं, जब भूकंप में काठमांडू घाटी एवं अन्य 9 जिलों की लगभग 50 फीसदी इमारतें धराशायी हो गईं और करीब 10 हजार लोगों को जान गंवानी पड़ी. आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना तो कल्पना से परे है. इमारत निर्माण के नियमों का पालन किए बिना बने भवनों ने इस भूकंप में कई लोगों की जान ले ली. 'नेशनल सोसाइटी फॉर अर्थक्वेक टेक्नालॉजी, नेपाल' के कार्यकारी निदेशक आमोद मणि दीक्षित कहते हैं, ''इमारतों का निर्माण उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए. आप बड़ी नदियों के किनारों पर 15 मंजिला इमारतें नहीं बना सकते. बड़ी इमारतें उन्हीं जगहों के आसपास बनाई जानी चाहिए जहां द्रवीकरण की प्रक्रिया धीमी है.'' काठमांडू घाटी में कई मकान सिर्फ ठेकेदारों के निर्देशों के आधार पर बने थे और इस दौरान अभियंताओं से सलाह तक नहीं ली गई थी. काठमांडू नगरपालिका के एक अधिकारी ने कहा, ''यह दिखाता है कि लोगों में जागरूकता काफी कम है और संभावित खतरे की उन्हें ही जानकारी नहीं है.'' काठमांडू में हर कहीं सीमेंट की चौखटों के इस्तेमाल का चलन है. कुछेक ही ऐसी भव्य इमारतें हैं, जिनका निर्माण वाकई गुणवत्तापूर्ण है. पुराने शहर में कई तंग गलियां हैं और उनके ऊपर भी इमारतों की बालकनी देखी जा सकती है. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढाकल कहते हैं, ''बचाव कार्य करने वाली टीमें अब भी काठमांडू की सघन आबादी वाली एक बस्ती में पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं. शोभाभागबती इलाके में छोटी गलियों में इमारतें धराशायी होने की वजह से बचाव टीमें क्षेत्र में पहुंचने में अब तक नाकाम रही हैं.''

यहां कई इमारतें ऐसी हैं, जिनका निर्माण 1934 में आए भूकंप के बाद मलबे से निकली ईंटों और लकड़ियों से किया गया है. हर भूकंप के बाद लगभग ऐसा ही होता आया है. शायद इनमें से कई भवन वर्ष 1833 के विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे से निकली ईंटों से बने हुए होंगे.

जापान जैसा विकसित राष्ट्र भूकंप की तबाही से जल्द उबर सकता है, लेकिन विकास में पहले ही पिछड़े नेपाल को ऐसी त्रासदी से उबरने में लंबा वक्त लगता है. भारतीय उपमहाद्वीप भूकंप के खतरेवाले क्षेत्र में आता है और यहां किसी भी समय एक बड़े भूकंप की आशंका बनी हुई है. इसलिए पहले से ही एहतियात बरतने की जरूरत है. यह बेहद आवश्यक है कि इमारत निर्माण के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए.

यह हकीकत है कि 'भूकंप लोगों को नहीं मारते, बल्कि लापरवाही से बनाई गई इमारतें उन्हें मारती हैं.' इमारतों और अन्य मकानों के घटिया निर्माण के कारण ही नेपाल में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई. काठमांडू में हर साल लगभग 6 हजार नई इमारतें बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां निर्माणकार्य की गुणवत्ता के प्रति नजरिया नहीं बदला है और इस बारे में नहीं सोचा गया है कि किस तरह उन्हें सुरक्षित बनाया जाए.

व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा

हालात से निपटने के लिए सरकार को व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा और साथ ही इमारत निर्माण के नियमों के पालन की निगरानी क्षमता बढ़ानी होगी. सरकार इस सिलसिले में इंजीनियरों और मकान बनानेवालों को प्रशिक्षण दे रही है. इमारत निर्माण के नियमों का पालन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है.

नेपाल को एक मजबूत देश बनाने के लिए ठेकेदारों और भवन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. निर्माण उद्योग की सक्रिय सहभागिता के बिना और सुरक्षित निर्माणकार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बिना मनचाहा बदलाव नहीं आ सकता. महार्जन और गुरुंग के अनुभव से पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों की जागरूकता को लेकर है, ताकि वे अपनी भूमिका बेहतर तरीके से अदा कर सकें. एक सुरक्षित मकान का निर्माण एक बेहतर दीर्घकालिक निवेश है, जो आपके परिवार और संपत्ति को किसी भूकंप से बचा सकता है. यह पसंद की बात नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है. ■■

भारत का नाम बदनाम ना करो

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

'घोटालों का देश' या 'कुशल कारीगरों का देश' अथवा 'महान संस्कृति का देश-भारत?' दुनिया हमें किस रूप में पहचाने? पहचान बनाने या बिगाड़ने के लिए भारतीय मूल का हर व्यक्ति यश-अपयश का भागीदार हो सकता है. फिर प्रधानमंत्री तो संपूर्ण भारत के सर्वोच्च प्रतिनिधि माने जाते हैं. मई महीने में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं. इस बार मंजिल मंगोलिया, दक्षिण कोरिया तथा चीन है. 1991 से 2014 के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया और चीन की यात्रा की. उन देशों के भी शीर्ष नेता भारत आए. इन यात्राओं के दौरान चीन तथा दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेताओं, प्रमुख राजनयिकों तथा नामी कंपनियों के उद्यमियों, निवेशकों ने भारत की अद्भुत क्षमताओं, गौरवशाली संस्कृति, लोकतांत्रिक सफलताओं की सराहना की. राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी की यात्राओं के दौरान भी प्रवासी भारतीयों ने शानदार आत्मीय स्वागत समारोह आयोजित किए. उन कार्यक्रमों में भारतीय संगीत व कला से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया. हां, पश्चिमी तर्ज पर 'रॉक शो' की तरह धूम धड़ाका नहीं हुआ. न ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने 'बदनाम भारत' जैसी चर्चा की. लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली यूरोप तथा कनाडा यात्रा के दौरान अपने चुनावी अभियान की नारेबाजी की तर्ज पर 'भारत की छवि' स्केम इंडिया' (घोटालों वाला भारत) जैसी गाली दे दी. निश्चित रूप से इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि पिछले वर्षों के दौरान भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले बड़े राजनीतिक मुद्दे बने. नाराज जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी को कड़ा सबक सिखाया. लेकिन यह पहला अवसर नहीं है. बोफोर्स तोप खरीदी कांड भी चुनावी मुद्दा बना था और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी. लेकिन भ्रष्टाचार, घोटाले किस देश में राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते? फिर भारत में भ्रष्टाचार के स्रोत क्या वही यूरोपीय, अमेरिकी, एशियाई देश नहीं रहे हैं? अपने हथियार और सामान बेचने के लिए उन्हीं देशों से एजेंट और धन आता-जाता रहा है.

सवाल यह है कि जब बराक ओबामा भारत आए, तो क्या उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 'सैक्स कांड' से हुई बदनामी या रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में हुए भारत विरोधी अभियान की भर्त्सना की? चीन के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान अपने अप्रवासी चीनियों के साथ बैठकों में क्या उनके पूर्ववर्ती सत्ताधारियों द्वारा किए गए जुल्मों की आलोचना करते हुए बदलते चीन के लिए अपनी जय जयकार की? दूसरी तरफ मोदी जी के सलाहकारों ने कभी इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश ही नहीं चीन और रूस में भी शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में दंडित होते रहे हैं. उनके घोटालों की रकम भारत से हजार गुना अधिक रही है. लोकतंत्र में तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई और जागरूकता जरूरी है. नरेंद्र मोदी या अन्ना हजारे या सीताराम येचुरी अथवा शरद यादव अथवा राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भारत में कितना ही बड़ा आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन 80 प्रतिशत गरीब जनता के अपने संपूर्ण भारत की छवि 'भ्रष्ट और बदनाम' रहने की बात करना क्या अशोभनीय नहीं है?

> नरेंद्र मोदी या अन्ना हजारे या सीताराम येचुरी अथवा शरद यादव अथवा राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भारत में कितना ही बड़ा आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन 80 प्रतिशत गरीब जनता के अपने संपूर्ण भारत की छवि 'भ्रष्ट और बदनाम' रहने की बात करना क्या अशोभनीय नहीं है?

नरसिंह राव, इंदर कुमार गुजराल, केआर नारायणन, एपीजे. अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय समुदाय के बीच क्या कभी बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड अथवा 2001 के गुजरात दंगों की भयावहता और कालिख का जिक्र किया तथा उन पापों से हटकर 'नए पुण्य' वाले भारत के निर्माण की बात की?

ऐसा नहीं करना ही उचित है, क्योंकि सारे झगड़ों, उपद्रवों के बावजूद भारत के 99 प्रतिशत से अधिक लोग सांप्रदायिक मानसिकता से एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं. यदि एक प्रतिशत सांप्रदायिक उन्माद से ग्रसित होंगे, तो उसके लिए कतिपय राजनीतिक-सांप्रदायिक तथा राष्ट्रविरोधी तत्व जिम्मेदार हैं, जो भारत की एकता तथा सफलता नहीं चाहते. इंटरनेट और टीवी के युग में भारत की बिगड़ी छवि नहीं छिप पाने का दावा भी हास्यास्पद है. विदेश में बसे लोगों को भारत की गड़बड़ियों की चिंता रहती है, लेकिन परदेश में भारत की अच्छी छवि तो वे स्वयं बना रहे हैं. 1985 में अमेरिका ने राजीव गांधी को सुपर कंप्यूटर बेचने से इंकार कर दिया था. उन्हीं राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर क्रांति लाकर अमेरिका को सिलीकोन वेली में 40 प्रतिशत भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों की उपयोगिता साबित कर दी. पिछले 60 वर्षों में भारत में केवल बर्बादी और गंदगी रहने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 'अर्द्धज्ञानी' प्रचारकों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि पिछले 60 वर्षों में भारत में ही शिक्षा-दीक्षा पाने वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों ने ब्रिटेन-अमेरिका जैसे देशों को उन पर निर्भर बना दिया है. यदि वे डॉक्टर भारत आने की घोषणा कर दें, तो लंदन के हजारों लोग मृत्यु शय्या पर दिखाई देंगे. अमेरिका से भारतीय कंप्यूटर विशेषज्ञ पलायन कर दें, तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. दूर क्यों जाते हैं-17 वर्ष पहले हुए दूसरे परमाणु परीक्षण भी क्या कोई घोटाला था? बांग्ला देश के समय अथवा कारगिल युद्ध के दौरान मुंहतोड़ जवाब कोई 'गंदा' काम था?

जर्मनी और चीन के कुछ विश्वविद्यालयों में भारत के संस्कृत और हिन्दी के साहित्य पर शोधपूर्ण कार्य कम से कम 50 वर्षों से चल रहे हैं. नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की आर्थिक दिशा को पश्चिमी देश नमन करते हैं. इन उपलब्धियों पर अहंकार न सही, कतिपय कमजोरियों और गड़बड़ियों पर भारत को बदनाम तथा कमजोर करने की कोशिश तो न की जाए. सत्ता का अहंकार बड़े बड़े तानाशाह को नष्ट कर देता है. लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार किसी अपराध से कम नहीं है और जनता स्वयं ही दंड तय कर देती है. ■■

जोखिम उठाएं तो अवसर अवश्य मिलेंगे

स्मार्ट स्ट्रीट
बिजनेसमैन

प्रकाश बियाणी
कॉर्पोरेट इतिहासकार

स्वयंभू समाजसेवी, राजनेता ही नहीं अकसर अभिनेता तक यह दावा करते हैं कि महिला सशक्तिकरण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है. सच यह है कि न्यू-एज शिक्षित व आत्मनिर्भर महिलाओं ने साबित किया है कि वे पुरुषों से कम नहीं बल्कि बेहतर हैं. ऐसी ही वुमन एक्जीक्यूटिव हैं फेसबुक इंडिया की हेड कीर्तिका रेड्डी.

एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी कीर्तिका रेड्डी के पिता सरकारी नौकर थे. उनका हर दूसरे-तीसरे साल ट्रांसफर होता था. कीर्तिका ने इसलिए डांडेली व नांदेड़ी जैसे छोटे टाउन्स में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया तो परिवार चौंक उठा. मां-पिता ने उन्हें अब तक पड़ोस के स्कूल-कॉलेज में पढ़ाया था. कीर्तिका को उन्हें समझाना पड़ा कि वे वयस्क हो गई हैं और अपनी देखरेख कर सकती हैं. इसके बाद कीर्तिका परिवार की पहली युवती बनीं जिन्होंने स्टेनफोर्ड युनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला लिया.

कीर्तिका रेड्डी

कीर्तिका ने वहां से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और सिराक्यूस युनिवर्सिटी से कम्प्यूटर इंजीनियर की मास्टर डिग्री(एमएस) प्राप्त की. सिलिकॉन वैली में ही उन्हें पहली नौकरी मिली. सिलिकॉन ग्राफिक्स के उनके बॉस परेशान थे कि वे खुद को अपने जॉब तक सीमित नहीं रखती हैं. कंपनी को क्या चाहिए, इस सोच पर चलते हुए वे इतनी तेज दौड़ी थीं कि सिलिकान ग्राफिक्स की सबसे युवा और पहली महिला डायरेक्टर बन गईं. उन्होंने मोटोरोला में भी डायरेक्टर (प्रोडक्ट, मैनेजमेंट) की जवाबदारी संभाली और फोनिक्स टेक्नोलॉजीस में यूएसए, इंडिया, जापान, कोरिया व ताइवान की टीम को लीड करते हुए वे 35-36 वर्ष की उम्र में ग्लोबल बिजनेस वुमन बन गईं.

सन 2012 के बाद भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़ने लगे थे. इमर्जिंग इंडिया में फेसबुक यूजर्स के विस्तार के साथ एड-रेवेन्यू बढ़ाने की मंशा से फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग ने कीर्तिका रेड्डी को चुना. 2010 में पहले भारतीय कर्मचारी की हैसियत से उन्होंने फेसबुक के इंडिया चीफ का दायित्व संभाला. यहां स्कैच से शुरू किया. हर माह 20 लाख नए यूजर्स जोड़े. नौ भाषाओं में उन्हें परस्पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई.

कीर्तिका रेड्डी कहती हैं कि फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग का लक्ष्य है भारत में एक अरब फेसबुक यूजर्स. चार साल में उन्होंने इसी अनुपात से फेसबुक यूजर्स व विज्ञापन की आय बढ़ाई है और कई कारोबारी गठबंधन भी किए हैं.

भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 80 लाख से 10 करोड़ 80 लाख कर देने वाली फेसबुक इंडिया की चीफ कीर्तिका रेड्डी दो बेटियों की मां हैं. सिलिकॉन वैली (यूएसए) में सीनियर पदों पर काम करते हुए उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया. छोटी बेटी अरिया को जन्म देने के छह सप्ताह बाद वे जॉब पर लौट गई थीं. उन दिनों बिजनेस टूर पर जातीं तो बेटी को भी साथ ले जातीं. हर टूर में उन्होंने लोकल बेबीसिटर खोजी और वर्क मीटिंग में से समय चुराकर बेबी-फीडिंग की. कीर्तिका रेड्डी कहती हैं, ''मैं उन दिनों को भूली नहीं हूं. अब तो बेटियां बड़ी हो गई हैं. मेरी वर्तमान हैसियत पर उन्हें गर्व है.'' कीर्तिका ने साबित किया है कि महिलाएं एक समय में कई काम पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं. शर्त है- खुद रास्ते खोजें, बहाने न बनाएं.

फार्च्यून इंडिया की टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमन इन इंडिया सूची में शामिल तथा 100 आयकॉन्स ऑफ इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम मान्यताप्राप्त कीर्तिका रेड्डी मां-पिता, पति (देव) व दोनों बेटियां (आशना व अरिया) के सपोर्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं. वे कहती हैं कि महिलाएं मोर्चा संभालें. वे जोखिम उठाएं तो अवसर अवश्य मिलेंगे. वे बेस्ट करें, बेस्ट परिणाम मिलेंगे. ■■

तोल बोल

सारा देश जानता है कि ममता बनर्जी जुझारू योद्धा हैं. आज वह जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है.
■ डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री

जद (यू) के सांसद के.सी. त्यागी ने राज्यसभा में 'पुत्रजीवक' दवा को लेकर गलत जानकारी दी जो राष्ट्रीय अपराध और संवैधानिक पाप है.
■ बाबा रामदेव, योग गुरु

पाठकों के पत्र

रेल परियोजनाएं

वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ समेत महाराष्ट्र की कई रेल योजनाएं वर्षों से लंबित हैं और केंद्र सरकार का इरादा उन्हें आगे बढ़ाने या पूरा करने का दिखाई नहीं देता. रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने संसद में बयान दिया है कि ये योजनाएं आर्थिक रूप से लाभकारी नजर नहीं आतीं. जिन योजनाओं का आधा काम हो चुका है, उनमें भी केंद्र सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश कहलाता है. इसके बावजूद राज्य के अनेक इलाकों में रेल सुविधाओं का नितांत अभाव है. इसके फलस्वरूप राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है. सरकार का आर्थिक हानि-लाभ का पैमाना क्या है? क्या यात्रियों की संख्या ही तय करेगी कि ट्रेन चलना चाहिए या नहीं. रेल चलेगी तो विकास होगा और ट्रेन में यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ेगी. आखिर हम लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना पर चल रहे हैं. सरकार को आर्थिक हानि-लाभ से ज्यादा रेल सेवा के जरिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए.

■ कृष्णकांत मोखार 'निर्भीक' यवतमाल

इतिहास पर नजर 3 मई

साठ के दशक में 'टाइम' मैगजीन द्वारा भारत में पं. जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी सबसे प्रभावशाली शख्सियत घोषित वी.के. कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई 1896 को कालिकट में हुआ था. सन 1962 में भारत पर चीन के हमले के वक्त वह देश के रक्षामंत्री थे. सन् 1957 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने कश्मीर मसले पर आठ घंटे का सबसे लंबा लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाला भाषण दिया. मेनन को पं. नेहरू के भरोसेमंद साथियों में गिना जाता था. वह त्रिवेंद्रम, मिदनापुर, उत्तर बंबई (मुंबई) से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए. 1953 से 1957 तक वह राज्यसभा के सदस्य थे. मेनन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी थे. सन् 1957 से 1962 तक वह देश के रक्षा मंत्री रहे. चीन के साथ युद्ध के बाद उन्हें पदत्याग करना पड़ा. 6 अक्तूबर 1974 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया. ■■

- 1481-ग्रीस का शेड्स द्वीप भूकंप से नष्ट, 30 हजार लोगों की मौत
- 1896-पूर्व रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन का जन्म
- 1913-भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन
- 1939-नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की
- 1981-अभिनेत्री नर्गिस का देहांत
- 2002-राजस्थान के बैंक ऑफ राजस्थान की इमारत पर मिग-21 विमान गिरा, 8 मरे

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XS©m
M`a_Z, E{S>Q>m[a`b ~moS>© : {dO` XS©m
E{S>Q>a-BZ-Mr\$: amOoÝÐ XS©m
gnmXH : {dH$mg {_l
{Zdmgr gnmXH$: Xde RmH$a★
★ nr. Ama. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ed H$ {bE {Oå_Xma.
© लोकमत समाचार àH$m{eV g^r g_Jr H$m gdm{YH$ma bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ nmg gw{jV h.
bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmH$_V _r{S>`m àm. {b., bmH$_V ^dZ, ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÝS>ñQ>r`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJna _ _{ÐV Ed bmH$_V g_mMma H$m`mb`, g~\$m_m {~pëS>J, ~S>~Z, qNXdmS>m _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. : MPHIN/2014/55600
XaÜd{Z : 07162-244081 \$°Šg : 07162-248081
Email : gnmXH$s` : lsedit.cwa@lokmat.com
df : 2, AH$ 44